**SC/ST and OBC Families below the poverty line in Santhal Pargana and Chhotanagpur Region**

1136. SHRI JANARDAN YADAV: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) the number of families belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes and Other Backward Classes, living below the poverty line particularly in Santhal Pargana and Chhotanagpur region, as on 31st December, 1995;

(b) whether the number of those families has been increased or decreased in comparison to the last year;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) the details of measures taken by Government to bring these families above the poverty line?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI BALRAM SINGH YADAV): (a) to (c) The Planning Commission estimates State-wise number of persons below poverty line on the basis of quinquennial survey on Household Consumer Expenditure conducted by the National Sample Survey Organisation (NSSOP). The data are collected for SC/ST separately but not for other socio-economic categories. The poverty estimates for Other Backward Classes are not available. The Statewise poverty estimates for SCs and STs are available only for the years 1977-78 and 1983-84. The data are not available below the level of the State. As such, the estimates of poverty for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Otrher Backward Classes in Santhal Pargana and Chhotanagpur region as on 31st December, 1995 are not available.

(d) A number of programmes are being implemented in order to improve the quality and life of the poor households. Of these, Integrated Rural Development Programme (IRDP), Training of Rural Youth for Self-Employment (TRYSEM), Development of Women and Children in Rural Areas (DWCRA) Jawahar Rozgar Yojana (JRY) and Employment Assurance Scheme (EAS), Drought Prone Area Programme (DPAP) and Desert Development Programme are being continued.

**संसदीय परामर्शदात्री समिति की सिफारिशें**

1137. **श्री अनन्तराम जायसवाल:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति ने सरकार से देश भर में कामगारों तथा विशेष तौर पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को एक समान न्यूनतम वेतन देने की सिफारिश की है, और

(ख) यदि हां, तो एक समान वेतन के अतिरिक्त अन्य किन-किन मुद्दों पर समिति ने सिफारिश की है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार समिति की इन सिफारिशों पर कब तक निर्णय लेकर उन्हें कार्यान्वित करेगी?

**श्रम मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी):** (क) और (ख) श्रम मंत्रालय को संसदीय परामर्शदात्री समिति ने 22.1.96 को हुई बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशें की थीं:

(i) सभी राज्यों पर लागू होने वाली एक समान न्यूनतम मजदूरी नियत करना।

(ii) कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी और अल्प रोजगार की स्थिति के मूल्यांकन हेतु एक अध्ययन करना।

(iii) केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यकरण के संबंध में एक टिप्पणी परामर्शदात्री समिति के सदस्यों को परिचालित की जाये।

जहां तक (i) का संबंध है, देश में समग्र रूप से सबसे निचले स्तर की एक न्यूनतम मजदूरी नियत करने के मुद्दे पर विचार-विमर्श के लिए सरकार ने 2 अप्रैल, 1996 को राज्य श्रम मंत्रियों और अन्य संबद्ध व्यक्तियों के साथ एक बैठक बुलाई है।

जहां तक (ii) का संबंध है, योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन पांच वर्षीय आधार पर रोजगार और बेरोजगारी से संबंधित सर्वेक्षण करता है। पिछला ऐसा सर्वेक्षण,